



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रोधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 14, 1976/चैत्र 25, 1898
No. 144] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 14, 1976/CHAITRA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April 1976

G.S.R. 293(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, No. G.S.R. 411 (E), dated the 15th September 1972, the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts citizens of India, against whom proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by them are pending before a criminal court in India and who produce orders from the court concerned permitting them to depart from India, from the operation of the provisions of clause (f) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, subject to the following conditions, namely:—

- (i) the passport to be issued to every such citizen shall be issued only for the period, if any, specified in the order of the court referred to above, or if no period is specified in such order, the passport shall be issued for a period of six months and may be renewed for a further period of six months if the order of the court is not cancelled or modified;
- (ii) the said citizen shall give an undertaking in writing to the passport authority that he shall, if required by the court concerned, appear before it at any time during the continuance in force of the passport so issued

[No VI/401/50/72]

K. R. NARAYANAN, Secy

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1976

सां. कां. निं. 293 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 411 (ई) दिनांक 15 सितम्बर, 1972 के अधि-क्रमण में, केन्द्र सरकार, इस विचार से कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा भारत के उन नागरिकों को, जिनके विरुद्ध किसी अपराध के आरोप में भारत की किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहा है और जिन्होंने सम्बद्ध अदालत से भारत से जाने की अनुमति के आवेदन प्रस्तुत किए हों, निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (2) के खण्ड (च) के प्रावधानों से छूट प्रदान करती है, यथा :—

- (i) ऐसे सभी नागरिकों को सिर्फ उसी अवधि, यदि कोई हो, के लिए पासपोर्ट जारी किया जायेगा जिस अवधि का उपरिलिखित अदालत के आदेश में उल्लेख हो, यदि उक्त आदेश में अवधि का उल्लेख न हो तो छह महीने के लिए पासपोर्ट जारी किया जाएगा और यदि अदालत के आदेश रद्द अथवा परिशोधित न हुए हों तो उसे अगले छह महीने के लिए नवीकृत किया जा सकता है ;
- (ii) ऐसा नागरिक पासपोर्ट प्राधिकारी को लिखित रूप से एक प्रतिज्ञा-पत्र देगा कि यदि संबद्ध अदालत उसे बुलाए तो इस तरह जारी किए गए पासपोर्ट के मान्य रहने के दौरान किसी भी समय अदालत के समक्ष वह हाजिर होगा।

[सं० VI/401/50/72]

के० आर० नारायणन्, सचिव।